



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 22 जुलाई, 1995/31 आषाढ़, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 10 जुलाई, 1995

संख्या आयु० बी०(10)-2/90—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, गुलशन कुमार, सहायक निदेशक को दिनांक 30-11-95 ने अधिवार्षिक की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त होने के सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,

जे० पी० नेगी,
आयुक्त एवं सचिव।

पंचायती राज विभाग

राज्यीय आदेश

शिमला-2, 1 जुलाई, 1995

संख्या पी0 सी0 एच-एच0 ए0 (5) 55/93.--प्रहृति श्री खेती राम, प्रधान, ग्राम पंचायत चान्ज, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा को उपायुक्त चम्बा के आदेश संख्या पी0 सी0 एच0-सी0 एच0-10(53/95)-982-86 दिनांक 13 जून, 1995 द्वारा प्रधान पद से निलम्बित किया गया।

और यह कि उपायुक्त चम्बा से प्राप्त रिपोर्ट तथा मामले की गम्भीरता को देखते हुए निलम्बन आदेशों की पुष्टि करना जनहित में उचित समझा गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (3) के अन्तर्गत प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उपायुक्त चम्बा के आदेश संख्या पी0 सी0 एच0-सी0 एच0-10(53/95)-982-86, दिनांक 13 जून, 1995 जिसके अन्तर्गत श्री खेती राम प्रधान, ग्राम पंचायत चान्ज, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा को निलम्बित किया है, की पुष्टि करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षर

कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव।

अधिसूचना

शिमला-171002, 1 जुलाई, 1995

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (4)-6/94.--इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 17 अप्रैल, 1995 के अन्तर्गत जिला मण्डी ग्राम सभा क्षेत्र को विभाजित/पुनर्गठित करने हेतु सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमन्त्रित किए गये हैं;

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर इस सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर उपायुक्त जिला मण्डी की सिफारिश के दृष्टिगत इस विभाग द्वारा जिला मण्डी के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्र के विभाजन एवं पुनर्गठन के सम्बन्ध में जारी पिछली सभी अधिसूचनाओं को आंशिक रूप में संशोधित कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष, 1994 का 4) की धाराओं 3 (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मण्डी के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्र का विभाजन/पुनर्गठन कर उनके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 (1) के प्रयोजन हेतु निम्न प्रकार से ग्राम सभाओं की स्थापना सहर्ष आदेशित करते हैं।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, यह भी आदेश प्रदान करते हैं कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्र का पुनर्गठन/पुनः सीमांकन वर्तमान ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों के अवसान तक प्रभावी नहीं होगा।

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम/मुख्यवास का नाम	कोष्ठ सं० 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ सं० 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों से बनी ग्राम सभा का नाम तथा उसका मुख्यवास	कोष्ठ सं० 5 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7

1. विकास खण्ड द्रंग :

1. मसौली	1. मसौली	1. दारट बगला	1. दारट बगला	कोष्ठ सं० 4 में वर्णित ग्राम	कोष्ठ सं० 4 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर कोष्ठ सं० 3 के शेष ग्राम वर्तमान ग्राम सभा "मसौली" में ही रहेंगे।
	2. छतर	2. जल प्रेहड़	(दारट बगला)		
	3. खदर	3. भंजवाड़ी			
	4. कौल	4. घमरेड़			
	5. झलवाण				
	6. पलहून				
	7. डी० पी० एफ० जालपा				
	8. दारट बगला				
	9. जलप्रेहड़				
	10. भंजवाड़ी				
	11. घमरेड़				

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 1 जुलाई, 1995

संख्या पी० सी० एच०-एच० एच० (5) 21/95.—यह कि उपायुक्त सोलन ने दिनांक 23-2-95 द्वारा यह सूचित किया कि श्री जिना लाल पंच ग्राम पंचायत वाकना विकास खण्ड कण्डाघाट, जिला सोलन को माननीय प्रतिनिक्त दण्डाधिकारी कण्डाघाट द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10-8-94 अनुसार हिमाचल प्रदेश में लागू पंजाब आवकारी नियम के अन्तर्गत दोषी अभियुक्त करार करते हुए एक हजार रु० जुर्माना व न्यायालय उठने तक कैद की सजा सुनवाई है जिस पर दोषी पंच द्वारा इस फैसले के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की गई है।

यह कि उपरोक्त पंच का यह कृत्य अशोभनीय है तथा इस कारण पंचायत की गरिमा को ठेस पहुंची है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146(1)(ख) के अन्तर्गत प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री जिना लाल पंच ग्राम पंचायत वाकना, विकास खण्ड कण्डाघाट को ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें उपरोक्त कृत्य के लिये उनके पद से हट/वदच्युत किया जाये,

उनका उत्तर इस नोटिस के जारी होने के 15 दिन के भीतर उपायुक्त सोलन के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

हस्ताक्षरित/-

अतिरिक्त सचिव एवं निदेशक।

शिमला-2, 1 जुलाई, 1995

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0ए0(5)-31/90. —श्री रणदीप सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत कोटी धीमान, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर के विरुद्ध पुलिस थाना रेणुका जी में दिनांक 24-6-93 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी जिसमें आरोप है कि प्राथमिक पाठशाला कोटी धीमान के पुराने भवन को बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति से गिरा कर उसका सामान खुर्द-बुर्द कर दिया।

यह कि पुलिस थाना रेणुका में मामले की मोका की छानबीन की और श्री रणदीप सिंह प्रधान को जुर्म जरे धारा 3(2) "ए" प्रीवेंशन ऑफ डैमेजिंग पब्लिक प्रोपर्टी अधिनियम, 1984 का साबित होने पर गिरफ्तार किया गया जो बाद में वर जमानत मुक्तका पर बरप्रदान रिहा हुआ है और चालान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत में प्रस्तुत किया गया है।

यह कि उपायुक्त सिरमौर से भी इस बारे रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि "प्रशासन जनता के द्वारा" कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त पंचायत के दौरे के समय श्री रणदीप सिंह ने प्राथमिक पाठशाला के भवन के नव-निर्माण हेतु राशि मांगी थी तथा वह पुराने भवन को गिरा कर नया भवन बनवाना चाहते थे। उन्हें राशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया था तथा उसे पुराने भवन को गिराने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने बारे कहा गया था।

यह कि रणदीप सिंह ने श्री मित्र सिंह तौमर का नाम ग्राम पंचायत कोटी धीमान के परिवार रजिस्टर भाग 1 से काट दिया था जिसके लिए वह सक्षम न थे।

और यह कि वर्गित वारों में तथ्यों की वास्तविकता को जानने व मामले में पूरी स्थिति सामने लाने के लिए सरकार द्वारा नियमिता जांच करवाने का जनहित में निर्णय लिया गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उन शक्तियों के द्वारा जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अधीन प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री रणदीप सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत कोटी धीमान, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता जानने के लिए उप-मण्डलाधिकारी (नॉ0) नाहन को जांच अधिकारी, नियुक्त करने के महर्ष आदेश देते हैं। साथ ही जिला अंशेक्षण अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर को प्रस्तुत अतिरिक्त अधिकारी भी नियुक्त किया जाता है जो जांच अधिकारी के सम्मुख सरकारी पत्र भी रखेंगे। यह भी आदेश दिया जाता है कि जांच का कार्य दो मास में पूर्ण करके जांच रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

हस्ताक्षरित/-

अतिरिक्त सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश।

[Authoritative English text of Govt. Notification No. 5-26/83-STV (TE)-Vol. II, dated 19-6-95 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th June, 1995

No. 5-26/83-STV (TE)-Vol.II.—In pursuance of the provisions of clause (IX) of sub-section (1) of section 4 read with section 6 of Himachal Pradesh Takniki Shiksha Board Act, 1986 (Act. No. 14 of 1986), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify the Names of S/Sh. Tek Chand MLA and Kuldip Singh Pathania, MLA elected by the Himachal Pradesh, Vidhan Sabha from amongst its members on the 30th March, 1995 to be the member of the Himachal Pradesh Takniki Shiksha Board for the remaining period of the Himachal Pradesh Takniki Shiksha Board with effect from the date of publication of the notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,

S. S. PARMAR,
Commissioner-cum-Secretary.

